

(Shri H. Hanumanthappa)

allowing you, please sit down. (Interruptions)... No, no. (Interruptions)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: \*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Your own Member was disturbing you. Please sit down. (Interruptions)... I am not allowing you. (Interruptions)...

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: \*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Ramachandran, please sit down. (Interruptions)... Nothing is going on record. I am not allowing anything to go on record. (Interruptions)... No, no. Please sit down. When I am standing you should sit down. (Interruptions)... Please sit down. (Interruptions)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: \*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Ganesan, please sit down. (Interruptions)... Mr. Ramachandran, please sit down. (Interruptions)... No cross-talks. Please sit down. (Interruptions)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: \*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I am not allowing you. Please sit down. (Interruptions)... Nothing is going on record. No. Enough. Please.

We will now take up the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1992. Yes, Minister. No cross-talk. Mr. Virumbi, please sit down. (Interruptions). I have called the Minister. (Interruptions). Please sit down. Mr. Virumbi, you can't disturb the House like this. Please sit down. You can't disturb the proceedings of the House. (Interruptions). It is over. Mr. Virumbi, you came and approached the Chair that you wanted

\*No. recorded.

to say something, I have permitted and you have made your point. But your colleagues are indulging in cross-talks. (Interruptions). Please sit down. Will you please sit down? I have already called the Minister. Mr. Ramachandran, please sit down. Please keep quiet. (Interruptions). Will you listen to the Chair? You are not allowed. What you wanted to go on record, that is recorded, but not this. Please don't disturb the proceedings. Mr. Ramachandran, please sit down. Don't force the Chair. (Interruptions). Please sit down.

# THE PUBLIC PREMISES (EVIC-TION OF UNAUTHORISED OCCU-PANT'S) AMENDMENT BILL, 1992.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

Sir, I rise to move in this August House amendments to the Public Premises Act, 1971, for consideration and passing.

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 was enacted to provide for the eviction of unauthorised occupants from public premises including the premises of Government companies and those of corporations established by Central Acts and organisations specified in the Act.

Various State Governments have approached the Government of India for bringing their premises situated within Delhi and other Union Territory limits also within the purview of this Act since they have been finding it difficult to evict unauthorised occupants from their premises. The available legal provisions have been found to be very dilatory and time-

consuming. It is proposed to accede to these requests and include the premises of State Governments situated in Delhi and other Union Territories within the definition of "Public Premises" by amending Section 2(e) of the Act.

The Government of India have also experienced difficulties in evicting temporary allottees in guest houses, hostels, tourist homes and various other premises coming under the purview of the Central Government, Union Territories and statutory authorities including hostel accommodation under the control of the two House Committees in Delhi.

The Government of India, therefore, after carefully examining various aspects, have proposed that summary procedure for eviction of such unauthorised occupants with a shorter notice than the existing one has to be provided to enable the Government to ensure continuous availability of such hostel accommodation and to prevent their being unauthorisedly converted into long-term occupancy. A new Section (Section 3A) has, therefore, been proposed in the Bill to achieve this objective. Enabling amendments consequent to these amendments have also been proposed in Section 2 and Section 18.

I request that the Bill may be passed since the objectives are unexceptionable and the amendments intended to provide for better enforcement of the Act.

I now move the Bill for consideration and passing by the House.

The question was proposed.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA):** Now the motion is moved. We will continue discussion on this Bill after lunch. The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri-mati Jayanthi Natarajan) in the Chair.

**THE PUBLIC PREMISES (EVICT-  
TION OF UNAUTHORISED OCCU-  
PANTS) AMENDMENT BILL, 1992**  
—Contd.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-  
MATI JAYANTHI NATARAJAN):**  
We shall now take up the Public  
Premises (Eviction of Unauthorised  
Occupants) Amendment Bill, 1992.

**श्री महेश्वर सिंह :** (हिमाचल प्रदेश) :  
उपसभाध्यक्ष महोदय, जो पब्लिक प्रेमिसेज  
अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने  
इस माननीय सदन में चर्चा और पारित  
करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने  
के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक  
के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है  
कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने  
सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो  
सम्पत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित  
प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा  
में नहीं आती, इसलिये उनको इस विधेयक  
की परिभाषा में लाने के लिये यह संशोधन  
अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह  
भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित  
जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो  
विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके  
अतिथियों को कुछ समय के लिये दिये  
गये थे आज उनको खाली करवाना भी  
सरकार के लिये एक टेढ़ी खीर बन गया  
है। इसलिये भी यह संशोधन आवश्यक  
है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो  
ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया  
है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है  
और इस समय जो इस प्रक्रिया में रुकावट  
का प्रावधान है उसकी भी समाप्त करने  
की बात की गयी है।

[श्री महेश्वर सिंह]

जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था, क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और फ्लैट्स इयरमारकड हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिल कर के 90 से ऊपर नहीं जाती है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला अलाट नहीं होता, फ्लैट अलाट नहीं होता। मैं आपसे माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सब से ज्यादा उल्लंघन किया है तो मैं आपसे माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन्हीं के दल के लोग हैं। आज जो सरकारी बंगले विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनरल पूल से कराये पर लिये हैं उनकी स्थिति भी 1990 के आंकड़े जो मेरे पास हैं, वह इस प्रकार है। लगभग 11 बंगले कांग्रेस दल के पास हैं। इन सरकारी बंगलों का जो किराया विभिन्न राजनीतिक दलों से देय था वह 8 लाख रुपये बनता था और इस आठ लाख की राशि में से केवल कांग्रेस के जिम्मे उस समय 5,85,530 रुपये बनते थे। सब से कम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे बनता था, केवलमात्र 185 रुपये। आज मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे एक भी पैसा देय नहीं होगा। इसका श्रेय हमारी पार्टी के नेताओं को जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। इसलिए नियमों का पूरा पूरा तरीके से पालन किया जाता है। 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 450 ऐसे केसेज हैं जो

सबलेटिंग के सरकार के ध्यान में आए से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ऐ सबलेटिंग के केसेज में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है? जैसे मैं कह रहा था कि इस समय 800 बंगले और फ्लैट सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए जब इयरमारकड हैं तो यह समस्या क्यों? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा था कि 46 पूर्व सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से आज भी बंगलों पर कब्जा कर रखा है। उस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उस में कई ऐसे नाम हैं जिनको हम भलीभाँति जानते हैं। वह भी आज अवैध रूप से बैठे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से उनका वहाँ रहना रेगुलराइज कर दिया है। इसलिए यह सूची जो है केवल मात्र 46 नामों की है। हैरानी होती है कि इस सूची में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दो वर्ष पहले भगवान को प्यारे हो गये लेकिन आज भी बंगले में रह रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनकी आत्मा उस बंगले में रह रही है या कौन लोग आज भी इन बंगलों में रह रहे हैं? (व्यवधान)

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): I take strong objection to this. He is referring to Members who have expired. And as you know, Madam, certain Members of our party have expired and their families on compassionate grounds have been allowed to stay in their houses. This is highly unfair to level allegations against the families of Members who have expired. I take strong objection to this and suggest to the hon. Member, who is a responsible Member, to withdraw this remark.

श्री महेश्वर सिंह : मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई रिमार्क नहीं किया है उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने यह कहा है कि जब वे लोग इस संसार में नहीं हैं और जब ये बंगल सांसदों के लिए इयरमारकड हैं, अगर कम्पैशनेट ग्राउंड पर सरकार उनको कोई और जगह अलाट करना चाहे

तो उसका स्वागत है मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो बंगले, जो फ्लैट सांसदों के लिए इयरमाकर्ड हैं उनमें सांसद ही रहने चाहिए।

**SHRI VISHVJIT P. SINGH:**  
Madam, the hon. Member is going further. He is poking fun at members who are deceased that they are deceased and some other people have occupied. This is very wrong. This is highly incorrect. Purely on compassionate grounds their families have been allowed to live in. Do you want to throw the widows out? Do you want to throw the little children out? Do you want to throw the families out? Till they make their alternative accommodations, they won't go from there. This is very wrong.

श्री महेश्वर सिंह : मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज भी अवैध रूप से रह रहे हैं, और यह मंत्री महोदय के जवाब में है। उन्होंने रेगुलराइज नहीं करवाया है। अवैध रूप से रह रहे हैं। मैं इस माननीय सदन में नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन वे सूची में सम्मिलित हैं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTI NATARAJAN):**  
Let him speak.

श्री महेश्वर सिंह : इसके अतिरिक्त कुछ बंगलों के लिए यह कहा गया है कि कुछ लोग दिल के मरीज हैं, कोई फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर को सरकार एकोमोडेशन दे, उसे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार भूतपूर्व सांसदों को कहीं एकोमोडेट करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब ये 800 के 800 बंगले सांसदों के लिए इयरमाकर्ड हैं, मंत्रियों के लिए इयरमाकर्ड हैं तो ऐसे लोगों को अगर सरकार आवास सुविधा देना चाहती है तो बड़ी उदारता से कहीं और जगह दे लेकिन यह उचित नहीं है कि हम लोग जो इस सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, इस सदन से बाहर हो जाने के बाद इन

कानूनों का उल्लंघन करें। इसमें हम लोगों के भी उपहास का पात्र बनेंगे। आज जो इस माननीय सदन की आवास समिति है उसके सामने भी एक समस्या खड़ी है... (समय की घंटी)

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTI NATARAJAN):**  
You have to conclude now.

श्री महेश्वर सिंह : मैं यह भी एक सुझाव देना चाहता हूँ कि केवल मात्र यह विधेयक पारित करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए जो विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता हैं उनको अपनी आचार संहिता में यह बात लिख देनी चाहिए कि जो सांसद, सांसद न रहने के बाद भी इस प्रकार के बंगलों में अगर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**SHRI VISHVJIT P. SINGH:**  
Madam, this is a very long overdue Bill and yet, as the hon. Minister has made it clear in the Statement of Objects and Reasons, there are two very valid reasons for bringing this Bill. The first reason is the demand by the State Governments. The State Governments have lots of buildings outside the State which unfortunately get occupied over a period of time through allotment and are never vacated. It is impossible for the States under the present purview of the Public Premises Act to get those premises vacated. They have tried. The State Governments have been trying for countless years. In fact, some of the State Governments have been fighting it out right since 1948 or 1949—since the amalgamation of the princely States. Various accommodations which were within the control of the princely States were transferred to the States and those accommodations are still not vacated. They are fighting in the Courts. They have tried the Public Premises Act.

Yet, they have failed, it is only after all that, as a last resort, that they have approached the Ministry of Urban Development and asked for these special powers to be given so that they can get their properties wherever they are, vacated. This is a highly laudable objective and for this I want the whole House to be one—as we are the Council of States. This Bill is primarily meant for the States to get vacated that accommodation which is outside the respective States. It is for that reason that this House ought to pass this Bill unanimously—just purely on this very basis. The second part is the one which refers to the guest accommodation and the honourable Member has referred only to the second part and not to the first part.

The second part refers to the guest accommodation. We are all aware, and some of us, I am sure, are guilty of it. People from our constituencies come and ask for accommodation and we allow them the accommodation and we allow them to stay on and many of us have never even checked as to whether they have vacated those premises or not. And, Madam, I find that over the years, many units of accommodation are still with people who are not authorised. They stay there without paying any fees or rent and without any authorisation. I was shocked to see that in the Western Court, certain units have been sealed and some people have locked certain units and people have got even their cards printed as permanent residents of Western Court and also of the V. P. House! They originally got them as guest accommodation, but they have refused to leave. Therefore, I think, the Government has no other way but to take recourse to this drastic action of taking it out of the purview of the courts in order not to allow these people to misuse this accommodation which was given to them as guest accommodation.

This is so far as the Bill is concerned. It is a very laudable Bill

and, as I said, the objects are very clear. But that is not enough. I would like to sound a note of caution: This is not enough.

Madam, the previous speaker referred to the question of accommodation. I would like to give the House certain statistics.

Out of the total accommodation available with the CPWD, under Type I, there are 13,768 units which are available and the waiting list is for 6,239 units; in Type II, 20,512 units are available and the waiting list is for 11,994; in Type III, 21,522 units are available and the waiting list is for 10,291; in Type IV, 5,114 units are available and the waiting list is for 2,586; in Type IV Special, 128 units are available and the waiting list is for 300; in Type V, 1,938 units are available and the waiting list is for 1,857; in Type V-B, there are no units available. A special category has been created, but not even one unit is available and the waiting list is for 475; in Type VI, 503 units are available and the waiting list is for 537; in Type VII, 116 units are available and the waiting list is for 282; and in Type VIII, 97 units are available and they are occupied.

In Hostels, 1,424 double suites are available and the waiting list is for 644.

In the case of single suites with kitchen, 224 units are available and the waiting list is for 799.

In respect of single suits without kitchen, 129 units are available and the waiting list is for 138.

In the Working Girls' Hostel, 137 units are available and the waiting list is for 65.

These are the figures. It is time that the Ministry of Urban Development made some efforts to try and create some extra accommodation. This extra accommodation is highly

essential. It is not enough merely to say that the premises are not available, that there is a long waiting list, and so on. I know that, today, people who are entitled to a particular type of accommodation, have to take—I am talking about Government servants—two types below their entitled type, if at all it is available, and even that is not available. Why can't you change the entitlement? If no person who is entitled to a particular type, ever gets that type of accommodation, why don't you then reflect on the realities of the situation on the ground rather than go on some other basis and say that this will never be available? If it is not available, then change the entitlement.

The Government should make more accommodation available. Though the list looks very large, it is not that difficult. I am sure we can provide some kind of units for all. The second point that I would like to make is that it is not enough merely to put particular categories out of the purview of the courts. According to me, all public premises should be taken out of the purview of the courts. This is the only way to make this legislation effective. I would like to quote an example. I am talking about my personal example. My grand-aunt had donated one house to a local hospital in Kapurthala. The house was donated to a hospital. It is a large property. The Punjab Government has been fighting that case since 1962. We are now in 1992. 30 years have passed. It has gone under the Public Premises Act. It has gone under every other Act. Let me tell you that the house is still not vacated. It is for charitable purposes, to set up a TB hospital. And the Punjab Government is making all the efforts. And till today that house is not vacated in spite of the best efforts of the Government. All Government premises which come within the purview of the Public Premises Act should be taken out of the purview of the court. It is only then that you will be able

to make this Act really effective. Otherwise, this Act, through dilution, will not work. Thank you, Madam.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Then, what about that appeal under Section 9 of the original Act? That appeal has two stages, stay and delay. What will happen then to the summary trial?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTHI NATARAJAN): Dr. Bapu Kaldate.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: That is exactly what I am saying. You need to amend the Act to take it out of the purview of the court.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: That is why I say that there is no amendment in the present Bill....

भो विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : जो  
आपने कहा है वही मैंने कहा है। वही  
तो मैं कह रहा हूँ।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Therefore, I suggest that they should bring another Bill. Otherwise, it will have to be amended further.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: At the present juncture, for the limited objectives which are laid down, this present Bill is absolutely sufficient. At least, get this Bill through so that something can be done. Or, you want that nothing should be done? Let something be done. We are the representatives of the States. The States have represented. It is for that that this Bill is being brought. That is the primary objective of this Bill to get those accommodations which belong to the States vacated. It is our responsibility as Members who represent the States. This is the Council of States. Let us be alive to our responsibility. Thank you, Madam.

डॉ० बापू कालदत्त (महाराष्ट्र) :  
उपसभाध्यक्ष जी, मैं सीमित दायरे की ही बात कहूंगा। माननीय विश्वजित पृथ्वीजित सिंह जी उन्होंने काफी इसका परिप्रेक्ष्य बढ़ाने का सुझाव दिया, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जहाँ तक इस विधेयक का सीमित दायरा है इस हद तक, मैं उद्देश्यों के हद तक इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ और मेरे ख्याल से यह सारा सदन जिस सीमित दायरे में इस विधेयक को पेश किया है उसका समर्थन करेगा, जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, क्योंकि मैं खुद आवास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ तथा मैंने खुद आवास देखे हैं। यह वर्टन कोर्ट देखा है, नार्थ एवेन्यू देखा सरप्राइज चैक जिसको कहते हैं और जो मुझे दिखाई दिया उससे मुझे भी लगा कि कोई एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जैसा कि मेरा अनुभव यह है कि पालिया-मेंट के मूबर्ज टैपोरैरी होते हैं, लेकिन उनके जो अतिथि होते हैं वे परमानेंट होते हैं। यह बात सही है।... (व्यवधान)... कई जगहों पर देखा है।

Members change but the guests remain the same.

लेकिन यह जिम्मेदारी हम लोगों की है Let me tell you very frankly। मैं हूँ इसके लिए जिम्मेवार, आप हैं इसके लिए जिम्मेवार। अगर हम इन लोगों को कोई न कोई मिल कर उसको अतिथि बनाने के लिए अगर उनकी मदद करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी सदन के सदस्यों की है और यह मैं नहीं चाहता कि हम उससे परे हैं। मैं हूँ या नहीं, मैं नहीं हूँ, यह भी मैं जानता हूँ और मैं उपदेश के तौर पर नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन सदन की गरिमा को अगर स्वस्थ रखना हो तो यह बात बिल्कुल साफ है कि सदन के सदस्य भी अपने-अपने दायरे में और नार्थस में काम करें नहीं तो ऐसा होगा कि हम यहाँ भाषण करके चले जाएंगे और हम ही दो-चार गेस्टों को एक्स्टेंड करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यह बात कभी नहीं होगी क्योंकि आवास समिति का प्रमुख आपका ही मित्र या सहयोगी

रहता है। आप चार लोग जाकर उसके पास बैठेंगे और कहेंगे—नहीं, नहीं, रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से शीला जी की हालत तो हमसे भी बुरी हो सकती है क्योंकि यहाँ तो राज्यसभा के लोग ही आएंगे, उनके पास तो सारे देश भर के लोग आते होंगे। मैं यह कहता हूँ कि यह एक अजब स्थिति है।

महोदय, हम वहाँ गए थे, हमारा फर्नीचर वहाँ पड़ा हुआ है। हम चाहते थे उसको बेचने की कुछ व्यवस्था करें ताकि लोग देखें और खरीद लें। तो गए नार्थ एवेन्यू। आप जाइए जरा नार्थ एवेन्यू अखबार वाले जब लिखते हैं कभी-कभी हम लोगों को गुस्सा आता है। लेकिन, लिखते सही हैं। आप जाइए नार्थ एवेन्यू। क्या वहाँ पीछे मैराज में टेंट हाऊस वाले नहीं रहते हैं। मैं देखकर आया हूँ। बहुत लोग रहते हैं, टेण्ट हाऊस वाले रहते हैं, घोड़ी तो शायद किसी के सर्वेण्ट क्वार्टर वाला हो सकता है, लेकिन टेण्ट हाऊस वाले, फर्नीचर की दुकान, होटल, रेस्टोरेण्ट है। ये लोग आपके दस्तखत से ही रहते होंगे। आप बताइए, किसने दस्तखत किए हैं? कैसे रह सकते हैं वहाँ? कोई न कोई मेम्बर जरूर दस्तखत करते होंगे। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस सदन की गरिमा, इस संसद के सदस्यों के बारे में अखबारों में इस तरह छपकर आ जाए कि वहाँ रेस्टोरेण्ट चलता है, वहाँ टेंट हाऊस चलता है? वहाँ और भी कुछ चलता होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन, इतना तो मैंने जरूर देखा है। तो इसके लिए भले ही अगर आपको अधिकार दे भी दें तो क्या इसमें हम लोग कुछ मदद करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो इस विधेयक से कुछ होने वाला नहीं है। सिंह जी, मैं आपको यह बात तो कह देता हूँ कि यह विधेयक तो ठीक है, कानूनी तौर पर ठीक है, लेकिन करेगा कौन इसको? यहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है, हम लोगों को ही करना होगा। अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे तो आपके विधेयक का कोई असर नहीं

होगा। यह बात मैं विनम्रता के साथ, लेकिन स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें जो डर है वह अलग है और मैंने कहा कि मैं आशंका के साथ इसका समर्थन कर रहा हूँ, उद्देश्यों का करता हूँ क्योंकि यह जरूरी है। एक नई फिजा अब सदनों के बीचों में, चल रही है कोर्ट में जाना। मैं सन, 1977 से इसी सदनों में रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सुना था कि लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आज आप एकमंडेशन कमेटी के चेयरमैन से पूछ लीजिए कि कितने मसले कोर्ट में गए हैं। कोर्ट बैचारा क्या करेगा? स्टे देगा। आप भले निकालने का प्रयास करें, लेकिन छह महीने तो कम से कम वह रहेगा क्योंकि जब नंबर आएगा उसके मुकदमे का तभी जाएगा। कभी कोर्ट में यह नहीं हुआ कि उनकी बात मान ली गई हो, जो भी कोर्ट में गए हैं कभी फैसला उनके पक्ष में नहीं हुआ, फैसला अपने ही पक्ष में हुआ है, लेकिन जाते हैं और छह-छह महीने उसमें लगते हैं। तो यह आवश्यक है कि समरी-पावर हो। यहां तक इस विधेयक का दावरा है उद्देश्यों की हद तक ठीक है, लेकिन मुझे इसमें पक्षपात का बहुत डर है क्योंकि वास्तविकता जो है वह कांग्रेस की दृष्टि से देखी जाए या सरकार की दृष्टि से देखी जाए तो मैं यह कहता हूँ कि बिल्कुल आपकी पक्षपाती है। मैं जानता हूँ गेस्ट-एकमंडेशन क्या है? नाम लेता अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे मित्र लोग हैं, हमारे बहुत परम मित्र लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप देखिए जरा। आप जरा इसकी फेहरिस्त देखिए कि कौन-कौन लोग, कहाँ-कहाँ, कितने-कितने सालों से हैं? इसमें मुझे डर यह है कि आपको तो हम पावर दे चुके और अगर आप इसमें पक्षपात करने लगे तो हो सकता है कि इस दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस वालों के रहेंगे, और किसी के नहीं रहेंगे।

श्री मातंग सिंह (असम) : सिर्फ कांग्रेस वालों के नहीं रहेंगे।

डा० बापू कालदास : अच्छा, वे भी जा सकते हैं। अच्छा गेस्ट उनके रहेंगे। अतिथि ही रहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन, इसमें बहुत जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। आप भले ही सरकारी पक्ष में बैठे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसकी दृष्टि इस बात को देखा जाए और सांसदों के वेतन के की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी इस कानून से आती है और हमारे जो लोग हैं, जो समितियाँ चलाते हैं, उनके ऊपर 3.00 P.M. भी आती है। अब मैं आखिर में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मरे यह सुझाव हैं। एक तो यह है कि आपके जो बंगले हैं वह बहुत पुराने हैं। मुझे मालूम है कि बरसात में क्या होता है। वह सब लोग डर गये होंगे जो पुराने बंगलों में रहते हैं। क्योंकि कब क्या मरेगा उसका कोई भरोसा नहीं। कुमारी आलिया जी अपने सदन को मेंबर थीं। बरसात में मैं उनके घर गया। एक भी कमरा नहीं था जहाँ वह बैठ सकती थीं। सारे कमरे पानी से भरे हुए थे।

श्री ईश वत्स यादव (उत्तर प्रदेश) : ऐसा मकान क्यों दिया आपने?

डा० बापू कालदास : मैंने नहीं दिया था। मैंने जयसवाल जी को दिया है। मुझे इसलिए मालूम है कि वह क्या है।

श्री संघ प्रिय गोतम : पक्षपात कर दिया आपने।

डा० बापू कालदास : बाबा खड़क सिंह मार्ग वाले जो प्लेट्स हैं वह बहुत अच्छे हैं और मैं मानता हूँ कि बजाय कि वह पुराने बंगले उनमें से कुछ बंगले तोड़ दीजिए और जैसे कि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जो आपने प्लेट्स बनाये हैं वह अगर प्लेट बना दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका एक प्लान बना दीजिए कि इतने सालों में हमको यह करना है। सिर्फ नाम के वास्ते ठीक है कि बंगले में रहने हैं, स्टेड्स भी हो, सकता है, शायद मुझे मालूम नहीं लेकिन आयोगा कोई तो उसको पता सकता है,



लगेगा कि इसका कोई स्टेटस नहीं इसलिए इसको बंगला दे दिया है। ऐसी हालत सब बंगलों की है। मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसा कोई स्कीम बनानी चाहिए ताकि आयन्दा कुछ सालों में यह मकान ऐसे फ्लेट्स बन जायें और यह भी लोग सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा कि अगर यह फ्लेट्स अच्छे हैं तो उसमें जाने का हम सब लोग प्रयास करेंगे।

मैं एक मिसाल देता हूँ। 1985 में कैबिनेट ने हक फैसला किया कि पार्टियों के लोगों को मकान देना चाहिए। फैसला यह था कि छः तक देना चाहिए। अब कांग्रेस के पदाधिकारियों और पार्टियों के पास कितने बंगले हैं, जरा देख लीजिए, कम से कम 14 हैं। कोई पार्टी यहां नहीं है, मैं रिक्रगनाइज्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ही अपने नियमों को तोड़ने लगेंगे तो शायद नियम चलेंगे नहीं।

**श्री अजीत जोगी :** (मध्य प्रदेश)  
कांग्रेस और दूसरी पार्टी में फर्क तो बहुत है।

**डा० बापू कालबाते :** वह तो हो सकता है। नियम आपने बनाये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो आपने नियम बनाए उसके ऊपर तो अनुपालन करो, आपसे मेरी यही मांग है। पक्षपात न हो, नहीं तो यह विधेयक बाकी लोगों के लिए एक खतरनाक विधेयक साबित हो सकता है। यह बात आप ध्यान रखकर इस विधेयक का हम समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ भी हमारे मन में जो आशंकाएँ हैं उसकी ध्यान में रखते हुए अपने काम को चलाएँ, इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** जोगी जी की बात का समर्थन करते हुए कि जितनी ज्यादा बड़ी पार्टी है उतनी खराबी ज्यादा है।

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU  
(Orissa); Madam Vice-Chairman,

keeping in view the laudable objectives of the Bill, I rise to support the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill. This Bill has been brought forward, as has been pointed out by the previous speakers, following the demand from the States that this legislation which is now in vogue in relation to the Central Government properties should be extended to cover the State Government's properties also to ensure eviction of unauthorised persons. It is very good that such a bold step has been taken.

While supporting this Bill, I would like to point out to the hon. Minister that we have, till now, touched only the fringe of the problem, Madam. Delhi is not just any other city. It is the Capital of India, People from all corners of the country, from far-off places, come to Delhi for various persons for administrative reasons, for health reasons etc. We have not paid sufficient attention to the fact that no cheap accommodation is available in Delhi. People find it difficult to get cheap accommodation when they come here from different places of the country. For example, many people come to the All India Institute of Medical Sciences, which is the best in the country. If a person has to undergo bypass surgery, he may have to stay in Delhi for months together because he does not know when the doctor will give the date for the operation. Similarly there are other reasons, administrative and other, for which one has to run to Delhi. There are not two opinions that unauthorised occupation must go. All the Members from different parties have said this but we must realise that Delhi is the capital of India. People from far off distances come here for various reasons. They are in search of a cheap accommodation. They cannot afford luxury of 5-star hotels which is meant for tourists and for those who can pay lavishly. No common man can afford such a costly accommodation. There-

fore, it is necessary that cheaper accommodation must be available for those who are coming to Delhi to get some medical treatment, to settle their administrative matters in head offices. This aspect has to be taken into consideration by the Government.

Madam, in this connection I would like to know two things. Firstly, very soon Delhi is going to have a State Legislature. The Bill has already been passed. I would like to know whether the Central Government would continue to be the evictor even after Delhi got its Statehood or whether the Delhi Administration will play the role of the evictor. It is necessary to consider this point.

Secondly, most of the hon. Members have suggested that it should be out of the purview of the court. This was necessary for expeditious action. But in the Statement of Objects and Reasons it has been said that "no appeal should be allowed against the order of eviction...". This is no good. It may tend to give arbitrary powers to the State Officer who is the sanctioning authority and who would also be the evicting authority. Nowhere in the world is there such a law. There is a possibility of the officials of the Estate Office colluding with the vested interests. We may ourselves be the victims because without our knowledge they may be allowed to stay in the guest house accommodation. So, this aspect of beneath-the-table may also be considered.

Let me again assert that there is a terrible population explosion in our country. People from various corners of the country are coming to Delhi. They are on the look out for a cheaper accommodation. They come here to get justice from Supreme Court, to get treatment in modern hospitals. Also, as Shri Vishvijit Singhji was saying, there is no proper accommodation for Government employees. Housing Development Scheme in Delhi has also not been successful. In

view of this, there will be pressure for unauthorised occupation, there will be pressure for getting accommodation in guest houses. Therefore, we have to go deeper into the problem. It is a burning problem to provide cheaper accommodation in Delhi. Therefore, I would like to appeal to the hon. Minister to consider this. You may keep it out of the purview of the court, but you must give the right to appeal. You must create some authority. Otherwise, the sanctioning authority, that is the Estate Officer, would be the evicting authority. It will become a quasi judicial body. From jurisprudence point of view, the executing body cannot be a judicial authority. It can never be a good law which creates all the authorities in one body. Hon. Minister may consider this aspect. It may create problems. It may pressurise some persons. Also, some persons may get favours and some persons may be harassed by the officers of the Estate Office. You may fix a limit of 7 days. The judgement must come within 15 days. It should not take 20 years. You may not give a long rope to the unauthorised occupants, who have no proper authority to continue. I was seeing the other provisions of the Bill and I will now try only to say that now you are trying to expedite the eviction by providing for only 24 hours' notice in clause 3 of the Bill. I say that at least seven days' time should be given and that should have been the proper time-frame. If people have remained for 20 years, can you not afford to give them seven days' time? Let us be very reasonable and rational when we pass a Bill like this. There is no question that within 24 hours we are going to solve the problem of housing in Delhi and it is not as if we are going to solve the problem of eviction within 24 hours. So, why should we create such provisions in the law which become arbitrary under the principles of legal jurisprudence? So, let us have all the regard for them. It might be only a temporary arrangement.

[Shri Santosh Kumar Sahu]  
The fundamental point is, when Delhi is going to become State, it will have another law. So what is the hurry for that? Therefore, I would like this fundamental point also to be considered.

Then, when we consider that Delhi is the capital of the country, development must take place here. There must be cheap and proper accommodation for people coming from the far corners of the country for justice, for administration and for medical treatment, because all these facilities are centred round here. Nobody can deny that.

With these few words, Madam. I think, in future the Urban Development Minister will kindly consider these points and see that a bold and ambitious plan is taken up for building new guest houses and cheap and proper accommodation because there will be pressure of people coming from different places. Thank you, Madam.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal):  
Madam Vice-Chairperson, to me it appears that this is a Bill which, on the face of it, is supportable and there is not much objection to be raised. But there are certain points which need to be brought before the House itself. To the purpose for which it is intended, we do not have any objection.

It is true that various State Government premises are under the occupation of people in an unauthorized manner in the Union territories. I support the idea that instead of keeping it only to the Central Government premises, State Government premises also are being brought within the purview of this Bill. But then, here I do support the proposals given by Shri Santosh Kumar Sahu about provision of cheap accommodation here. That will come later.

But what I find here is that besides the office premises—which is the pri-

mary concern of this Bill—I feel that residential premises of the Government like flats, bungalows and hostels—I think Dr. Bapu Kaldateji has also mentioned about it with his experience as Chairman of the House Committee of this House—are remaining occupied in an unauthorized manner. The surprising part of it is this. Dr. Bapu Kaldateji has also mentioned it. What we find is that ex-MPs and ex-Ministers are also retaining some of these accommodations under their thumb. At the time when they were holding offices they must have requested and got some allotment, but years and years have passed by but these ex-MPs and ex-Ministers are still keeping these accommodations under their control. I am not going to mention about it. Dr. Bapu Kaldateji is quite experienced and he has given a clear picture of it—and I fully endorse it because I also happened to be associated with him for quite some time on the House Committee. The problem today is, I do not find that there is any difficulty so far as the new Ministers are concerned. It is the Government's responsibility and Mantriji will be trying to go out of her way to provide accommodation for them, justifiably so. But what about the MPs?

DR. BAPU KALDATE: Old people are there.

SHRI ASHIS SEN: That is why Mr. Vishvijit Singh has given figures about how many are thus occupied and how many the claimants are. I am not going into those figures, to avoid repetition. But the question which comes here is, new MPs are coming. I don't think Mantriji is taking as much care about the accommodation of the new MPs who are coming. For months together they move about and they don't get accommodation. It cannot be provided to them. Flats and hostel accommodation in the name of having guest accommodation for a few days only, are kept under the control of the allottees for weeks and months. Even we have the expe-

rience that for two-and-a-half years in the Western Court in the name of this MP or that Minister or some other person like that somebody was kept there, with the result that new MPs could not get accommodation, and Ministers and MPs also who want to get an accommodation for their guests, could not get it. This is the state of affairs which perhaps cannot be reconciled with. That is why I do support certain proposals of this Bill. There are umpteen cases like this. Dr. Kaldate has already mentioned about it.

The surprising part of it is this. I happen to be an allottee in the V.P. House. There are a number of one-room flats, two-room flats allotted to certain individuals, guests of MPs. We find that other MPs are not getting accommodation. When nominees of MPs come for their medical attention or for admission for any other purposes, they are not being given accommodation which can possibly be given. These rooms and flats are being used by certain people for the weak-ends or as a rendezvous. Even today this is going on. On the other side we find the other aspect. I am not going to use any other word for that. I am confining myself only to the word "rendezvous." You can interpret it.

Certain rooms are lying locked for more than a year and a half. Still such rooms are there, flats are there. It is not a question of Western Court alone. The V.P. House also has hostel accommodation. I am bringing in the question of the V. P. House. Hostel-type accommodation is there, and the position in that respect is not different.

One thing comes in here that if public premises are under the occupation of unauthorised persons, it has been said that they should be taken out of the court. It is one way of saying that if they are taken out of the

court, there will be a speedy disposal of the disputes and removal of persons who are unauthorisedly occupying the premises for a long period. I am not a technical man. I do not know the law about these things. What I say is that an opportunity should be given to the person to whom notice is given so that he can represent or appeal against what has been demanded. Though, on the basis of experience in the House Committee, I find that perhaps that is not needed, natural justice demands that there should be an opportunity given to the person to represent or appeal.

Here is section 3A is given the procedure to be followed by the estate officer if he is of the opinion that any persons who were allotted temporary occupation of any public premises, are in unauthorised occupation of the said premises. We are giving to the executive too much power. I would like to put amendment in this form:

"If the estate officer finds on the basis of facts and documents, not because of his opinion alone....."

I may be prejudiced, I may be vindictive as an estate officer. That is why I say that on the basis of facts and documents if he feels that any person is in unauthorised occupation of some premises, then, he should be evicted under the procedure that has been laid down therein. Right. Why I feel so is that there is another point also. The Bill may be put through. But the power has to be given to the estate officer to evict such occupants by use of force. I do not know what the Minister has in her mind about this. On page 3 of the Bill it is stated that the estate officer can use such force as may be necessary. If this is not clearly explained here, then, the estate officer can take the responsibility of doing the job of a Police officer. Police officers use several types of degrees for getting certain things

[Shri Ashish Sen]

done. Such an event may develop here. We should take care that this does not happen. (Time bell rings). Another Member of the House Committee, Sahu Ji, has also spoken about it. People are coming here. Why should the Minister not please consider providing cheap accommodation in Delhi? People will be coming here for medical aid or for other purposes. If some modernised Dharmshalas are provided, the people coming to Delhi will not become a victim of big hotels. Why do we need so many five-star hotels? For Olympics it was done. It was quite all right. I am not disputing that point. But there is a need for construction of very many cheap accommodation and improved varieties of Dharmshalas in large numbers. If it is done, the Minister will be doing a good service to the people and they will be blessing her for this facility. I do not want to talk much about it any further, but what I want to say is this. Mr. Vizol, the ex-Chief Minister of Nagaland has been here for the past three months. I enquired where he was staying. I came to know that for the past three months he has been here, but he has not yet been allotted any bungalow. He is roaming about in the city of Delhi, but he does not have an accommodation. He is an ex-Chief Minister of a State. I think the hon. Minister will kindly look into it. Incidentally, though it may not be directly relevant here, yet I would like to refer to a case of the State I come from. In the city of Calcutta, I find very many Central Government offices are located. I am not saying some people should be evicted from there. What I say is that the Calcutta Municipal Corporation has repeatedly made appeals to the Central Government that at least taxes due from these buildings for occupation by them should be paid. If the Minister takes care of that, the Calcutta Municipal Corporation Mayor will be happy for getting crores and crores of rupees of out-

standing dues. Because it is the Council of the States and I am a Member from that State, I feel some problem of my State I should bring to the notice of the House, apart from the other things under the Bill on which I have already spoken.

**श्री ईश बत्त यादव :** मैडम सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक 1992 जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसके विरोध में नहीं हूँ बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यह कानून बहुत पुराना है। सन् 1971 में यह पास किया गया था और कानून बना था। थोड़ा सा परिभाषाओं में और कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है कि राज्य सरकारों के दिल्ली में और केन्द्र शासित प्रदेशों में जो भवन हैं उनमें अनधिकृत रूप से जो लोग रहते हैं उनको बेदखली के लिए सरसरीतौर से कार्रवाई की जायेगी, इस तरह का संशोधन किया जा रहा है। लेकिन यह जो संशोधन किया जा रहा है इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई फॉर्स नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि यह पुराना कानून 1971 का है और अब जो संशोधन किया जा रहा है ये दोनों भले आदमी के लिए है, शरीफ आदमी के लिए है, कमजोर आदमी के लिए है। जो बड़ा आदमी है, जो प्रभावशाली है, जनबल में मजबूत है उसके लिए यह कानून कुछ नहीं कर सकता। दूसरे इस संबंध में निवेदन यह है कि जो अधिकारी है या मंत्री है, माननीय शीला कौल जी से मेरा मतलब नहीं हूँ उनके स्थान पर जो भी मंत्री रहे हों या जो रहेगा, चाहे जिस दल का हों, उसकी नियत पर निर्भर करता है मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता।

**श्री सद्य प्रिय गोतम :** एक मंत्री वेस्टन कोट में भी रहा था।

**श्री ईश बत्त यादव :** मंत्री के विपक्ष के लोगों के लिए आदेश होते हैं कि आप तीन दिन में भवन खाली कर दीजिए और जो सरकारी पक्ष के हैं उनके लिए एक साल तक। उसके पीछे कभी पत्नी बीमार है तो कभी बच्चे की शिक्षा है, इस तरह के अनेक कारण हैं। मैं निवेदन

कर रहा था कि इस कानून का न कभी गहराई से पालन हुआ और न मुझे सम्भावना है कि इसका गहराई से पालन हो सकेगा। अगर माननीय मंत्री जी या इनके बाद जो भी मंत्री रहे जिस भी दल का हो, अगर इस कानून का गहराई से पालन करें तब तो इसका कोई लाभ हो सकता है। महोदया दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरा सदन जानता है कानून के जानकार लोग हैं, आप भी हाई कोर्ट की अधिकता हैं और मैंने सुना है कि योग्य अधिकता है, इस कानून से लाभ क्या होगा? संविधान का जो अनुच्छेद 226 है वेदखली की कार्यवाही करने में पहले ही जो आदमी अनधिकृत रूप में रह रहा है वह हाई कोर्ट में चला जाता है और स्टे ले लेता है, सिविल कोर्ट में पहले चला जाता है और स्वयं आदेश ले लेता है तो फिर क्या होगा? यह पूरा बिल मैं देख नहीं पाया हूँ लेकिन जो कुछ देख पाया हूँ उसमें मैंने कहीं भी यह नहीं पाया है कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट का तो संविधान संशोधन आप कर नहीं सकते हैं यादिकल 226 में रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इस कानून का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करना कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और जो कानूनी अड़ें आने वाले हैं कानूनी बाधाएँ आने वाली हैं, उन बाधाओं का निराकरण करके सरसरी तौर पर आप किस तरीके से वेदखली की कार्यवाही कर सकेंगे। अगर आप गम्भीरता में नहीं सोजेंगे और कानून में फिर संशोधन नहीं करेंगे तो इस संशोधन में मेरी राय में कोई लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे गेस्ट्स रहते हैं। यह ठीक है कि माननीय सदस्यों के गेस्ट्स रहते हैं। प्रोबलम्स हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप कुछ भवनों का विस्तार कराइये कुछ राज्‍य सरकारों को भी

प्रोत्साहित कीजिये कि वे दिल्ली में कुछ अपने भवन बना सकें। मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ। उत्तर प्रदेश के दो भवन यहां पर हैं और तीसरा भवन बन रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो एम० एल०एज० हैं, हमारे जो अधिकारी हैं या नव-निर्वाचित संसद सदस्य हैं उनको स्थान नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि कमरों की कमी है। दूसरी बात यह है कि आज ही माननीय मंत्री जी अपने आदेश में जांच करवायें या प्रदेश सरकारों में जांच करवायें तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश भवन में अनधिकृत रूप से सालों से लोग पड़े हुए हैं। वे न तो एम० एल० ए हैं और न ही एम० पी० हैं और न ही आई० ए० एस० या आई० पी० एम० अधिकारी हैं। उनको कोई वेदखल करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सरकार के और अधिकारियों की नियत पर निर्भर करना है कि कौन आदमी अनधिकृत व्यक्ति है और किसको निकाला जाय और किस को नहीं निकाला जाय। इस मामले पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और जैसा मैंने निवेदन किया माननीया मंत्री जी कुछ भवनों का विस्तार करायें। आपके पास वेस्टन कोर्ट और वी० पी० हाउसेज हैं। लेकिन फिर भी जगह नहीं है। मेरे जनपद से माननीय सदस्य श्री मोहम्मद मसूद साहब इस सदन में निर्वाचित होकर आये हैं। हफ्तों तक हमने प्रयास किया, उनको यू०पी० भवन में जगह नहीं मिली। बहुत प्रयास करने के बाद मैं हाउस कमेटी के चेयरमैन महोदय को अनुरोध देता हूँ उनको 12 नम्बर का कमरा मिला। लेकिन वह कमरा ऐसा है कि उसमें आदमी तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता है। यह कमरा उनको एलाट किया गया है। वह सदन के सम्मानित सदस्य है। उनको वेस्टन कोर्ट में 12 नम्बर कमरा मिला है... (व्यवधान)। महोदया जब आप वहां रहती थीं तो तब उसकी रौनक इसरी थी। दो साल के बाद उसकी रौनक खत्म हो गई है। वह कमरा

[श्री ईश दत्त यादव]

रहने लायक नहीं रह गया है। आज भी मैं उनके साथ हाउस कमेटी के चेयरमैन साहब के पास गये। हमने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश भवन में उनको एक कमरा दिलवा दिया जाय। उन्होंने आश्वासन दिया और अपने अधिकारी को निर्देश भी दिया। मुझे विश्वास है कि उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश भवन में शायद —मैं शायद कह रहा हूँ—उनको कमरा मिल जाये, वरना उनको उसी में रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि आप विस्तार करवायें। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदया और भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की समस्याएँ, जिनका जिक्र हमारे माननीय वक्ताओं ने किया है तो ऐसी समस्याएँ किस वजह से पैदा होती है? एक तो यह समस्या पैदा होती है भूत-पूर्व सांसदों के कारण... (तत्पश्चात् की घंटी)...

मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

एक तो भूतपूर्व सांसदों की वजह से यह समस्या पैदा हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया और सरकार से मांग करूँगा कि आप इस तरह की व्यवस्था करें जो वर्तमान सांसद हैं और जो दिल्ली में मकान लेना चाहें उसके लिए दिल्ली में एक छोटा सा भूखंड और कोई छोटा सा मकान, आपके कौन्सिल जो बनते हैं, वे, उनको आसान किस्तों पर अलॉट करवाइये ताकि वे उ को पांच सालों में, दस सालों में परचेज कर दें, इसी प्रकार की व्यवस्था आप पत्रकारों के लिए भी कर दें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कर दें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कर दें। और भी बहुत लोग हैं, दिल्ली बहुत बड़ी हो गयी है और अब इसकी करोड़ों की जनसंख्या होने जा रही है। सब के लिये तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में आप को बेदखल की

कार्यवाही की नौबत आती है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए। साधारण आदमी को तो आपका सिपाही जब चाहे उसका सामान बाहर फेंक देगा। लेकिन भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार, अगर इनके साथ ऐसा होगा तो अखबार में छाप देंगे। हम अगर भूतपूर्व हो गए तो क्योंकि हमें लड़ाई लड़ने का अनुभव हो गया है इसलिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार दिल्ली में सांसदों के लिए, पत्रकारों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए छोटे भूखंड आवंटित करें, फ्लैट आवंटित करें और उनको यह आसान किस्तों पर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस समस्या का निराकरण हो सकेगा और यह समस्या गंभीर नहीं हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस पर कड़ाई से पालन करेंगी। मैं आप को कोई शिकायत नहीं करना चाहता लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि सत्ता पक्ष के लिए आप का दिल जो है वह बड़ा नरम है लेकिन विरोधियों के लिए थोड़ा कड़ा है। उनको आप तीन दिन में हटा देती हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष के हैं उनकी औरत की बीमारी और बच्चों के स्कूल के कारण उन पर रियायत कर देती हैं। मैं एक छोटा सा आपसे अनुरोध करूँगा। शायद आपको आंकड़ें मिल जायें। आप अपने उत्तर में बतलायेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाली नहीं किया है और उनमें किस-किस दल के लोग कितने दिन से वहाँ पड़े हैं?

इन शब्दों के साथ मैं आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप ने मुझे इस पर बोलने का समय दिया।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, I rise to support the Bill. I appreciate

the intention of the Government in bringing this Bill, firstly, to help the State Governments to evict the tenants from their allotments in Delhi and secondly, to amend the existing provisions so as to evict persons from unlawful possession of Government buildings.

Madam, there are provisions existing to evict persons from unlawful possession of Government buildings. It has been noted in certain cases that it is not only the law which is standing against evictions but the will of the Government to evict such persons is also not there. And sometimes, when there are two similar cases, against one person action is taken and against the other action is not taken, for various reasons. Whatever may be the provisions available under the Act, the Government should also see to it that they are implemented properly. Without proper implementation, making the Act more and more stringent will not be of any use.

Regarding guest accommodation, I happened to read a House Committee report. The House Committee investigated the whole matter as to how many people were living in the Western Court and other places. And I hope, this Bill, after it is passed, will be able to help the Government to see that these people are evicted.

One point which I want to mention is regarding the allotment of servant quarters. Many of these public buildings are given to Members of Parliament and Government Officers and then servant quarters are also attached to these buildings. In a bungalow, there may be two, three, four or sometimes five servant quarters. When an M. P. or an officer is allotted a particular building, he gets in some servants for the work to be done in his bungalow and when a servant comes there—a house-maid or a servant—to work in the house, they do work in the house for some time. There are a certain set of peo-

ple who are always hankering for getting the accommodation of the M. Ps quarters especially, and also government officers quarters. After they come there and stay there for some time, they cease to work. They occupy the house, continue to be there but cease to work in the bungalow and when we want them to go out of the bungalow, they refuse to go out also. Now, what happens is that an M.P. remains in the bungalow for a period of five years or six years, depending upon the tenure of the Member. The servant is there and from one house of the M. P, he goes to another house of the M. P. This is what is happening here and no action could be taken. A similar case has also happened with me. A maid-servant was put in the servant quarter, She worked for some time. Later on, she married for a second time and refused to work in the House. When I asked her to go out of the servant quarter, she refused to go and got in more and more people there and created a lot of problem for us. I took up the matter at the Rajya Sabha Secretariat level. They say that no action can be taken because I as an M. P., got a servant in my servant quarter and before I get a servant, I should have carefully analysed whether that servant will be all right or not. Sometimes, it may not be possible for an M.P. from Tamil Nadu or from Kerala to verify all these things. When they get a servant, they may not know how the servant will behave afterwards, especially after getting a second husband, most probably, all the people are coming and we may not know that she will get herself married again. This kind of situations come and no action can be taken by M.Ps. Still, it is continuing.

Then, another course of action was suggested that this matter can be reported to the police that they are unauthorised persons and since they are unauthorised persons, they can be evicted by the police. When such a move is made to the police, the



[Shri G. Swaminathan] police say, it is a matter of civil nature and they will not interfere in getting the servant out and we should make some arrangements of our own. Now, an M.P. is not a legal owner of the house and when he lets out a servant quarter, he cannot legally move in the matter because he himself is a tenant and he has given that portion of the servant quarters to somebody else. When we report to the police, they feel, it is between the landlord and the tenant even though we are not the regular landlord. They say this matter is of a civil nature and they will not interfere and take any suitable action in this matter. This seems to be a regular lacuna which many of the MPs have told me and for the servants to go away you have to use muscle power and then you have to see that they go out of the house. This is the position. I would request the hon. Minister to find a way out for this thing.

Before I conclude, I wish to make only one or two points. One thing is about the old bungalows. I am living in one such old bungalow in Canning Lane. Most probably, it must have been 100 years old or 150 years old and is in a dilapidated condition. It has got about half acre area, it has a big garden. Everything is there. But these bungalows on some of the roads like Canning Lane are so old that they have become dilapidated. Recently when I got re-elected to Rajya Sabha, my wife asked me, "why can't you see and try to find out some other good house?" Yesterday I went about seeing many houses to find out whether I could request the hon. Chairman of the House Committee to get another house for me. When I went out to so many places, I am now convinced that my present place is better and it is not worse than most of the bungalows I have seen.

Almost all the bungalows which I was able to see except the Ministers bungalows or the bungalow of the Chairman of the House Committee—

these bungalows are done up well—are in a bad shape and I would request the hon. Minister to appoint a Committee of Members of Parliament—for Rajya Sabha Pool, a Committee consisting of Members of Rajya Sabha and for Lok Sabha, a Committee consisting of Members of Lok Sabha—to find out the facts, to go about and see all the bungalows, how bad a condition they are in. And they have to be rectified. At least some urgent action has to be taken. Ordinary repairs will not do. Urgent action has to be taken to see that these bungalows are properly kept. I may also incidentally mention that the service of the CPWD is very bad, they are not timely, they are also not doing their work properly. This matter has also to be looked into.

And only one word regarding the Baba Kharag Singh Marg. Some Member has said—I don't know if it is Bapu Kaldate or somebody else—that these Baba Kharag Singh Marg flats were built recently. Yesterday I happened to go there and I saw the flats. Some of my relatives are living in flats in Madras, constructed by private builders. Those flats are so nicely built that you don't feel that you are living in a flat. I don't know who gave you the plans for these Baba Kharag Singh Marg flats. It is all something like a vestibule. Some of our hon. Members had been there. . . (Interruption)... I don't want to tell their names. Some of the hon. Members told me. These flats were built six years ago when I came. Some hon. Members of the House immediately got some accommodation and went there and many of these Members who were allotted the Baba Kharag Singh Marg flats vacated the flats and went to some other place—I don't know whether they got better houses and went or they could not live in Baba Kharag Singh Marg flats.

Another thing, the structure and architectural construction of the flats

is no good. There is no washing area for utensils and clothes. We went yesterday—I just wanted to know, my wife also came with me—to see where the washing area is for utensils, the person who was living in flat said, “You have to wash your utensils only in the wash-basin.” Madam, in Indian conditions we don't have place where we can wash our utensils. Our wash-basins are so small. They are not so big as we see in other countries. There is no washing area for clothes also. This is the condition of these Baba Kharag Singh Marg flats... (Interruption) ... No, I don't want to mention names—Perhaps, she got a better house and went or she didn't like the place; I don't know what the reason is. I would only request the hon. Minister, “If you go in for flat construction, better consult good architects and see that you construct according to the needs of the people who live there. It should be constructed in such a manner. It has got big rooms; four bedrooms are there. Everything is there, but the construction is not useful. I would request the hon. Minister to take this into consideration when she goes in for further construction of flats instead of houses for Members of Parliament. Thank you.

श्री मोहम्मद खलीलूर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : मैडम वाइस चैयरमैन, द पब्लिक प्रेमिसेज (इविकशन आफ अनअथराइज्ड आक्युपेंट्स) अमेंडमेंट बिल, 1992 की मैं तारीफ करता हूँ कि इस वजह से यह कानूनी जरूरत है और मौजूदा हालत में बहुत जरूरी है कि यह बिल पास किया जाए मगर मैं आनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि पानी सिर से ऊंचा होने के बाद आप यह बिल लाई है ।

1971 में यह एक्ट बना था, गोया आज से 21 साल पहले । इस असे में कई ऐसे मजायज कब्जादार इन बिल्डिंग में आ गये । मगर इसके बावजूद 21 साल तक आप बैठे रहे । अब जब कि

मसला इतना ही बढ़ा और पेचीदा हो गया है तो यह बिल लाया गया है । खैर, देर आये दुस्त आये । एक अच्छा बिल है और इसलिए मैं इस बिल की ताहिद करता हूँ ।

यह जो बिल लाया गया है खास तौर से स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे प्रेमिसेज जो कि दिल्ली या यूनियन टेरिटरीज में है और स्टेट गवर्नमेंट का कानून यहाँ पर लागू नहीं होता, लिहाजा स्टेट गवर्नमेंट्स का एक जमाने से मतलब था कि इस कानून में इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस बात का अस्तियार दिया जाए कि यहाँ पर उनके जो प्रेमिसेज हैं वो उन प्रेमिसेज को खाली करा सके ।

इतिहाई कीमती जायदाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की है । मिसाल के तौर पर मैं आन्ध्र प्रदेश की ही बात करूंगा । जो यहाँ का हैदराबाद हाउस है वह इस वक्त मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नंबर एक गेस्ट हाउस है बल्कि मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बाद जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग इस वक्त दिल्ली में है वह हैदराबाद हाउस की है । यह स्टेट गवर्नमेंट की प्रापर्टी में है मगर इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट अन-अथराइज्ड तरीके से उस बिल्डिंग पर काबिज है । मैं आप से दरखास्त करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके फौरन हैदराबाद हाउस को आप स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दीजिए ।

खैर तोल्लक लिगिशन चल रहे हैं । मगर कानून बनाने के बाद मैं सम्झता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को यह हक मिल जाएगा कि वह हैदराबाद हाउस को तब्दिल कर सकें । यह बहुत अच्छा कानून है ।

फिर दूसरी बात, जैसा कि गेस्ट अकामोडेशन के ताल्लुक से कही गई है, यह जनरल शिकायत है और यह बिल्कुल सही है कि बाज ऐसे लोग किसी न किसी वजह से बीमारी की वजह से, बच्चों

[श्रीमोहम्मद खलिलुर रहमान]

को तालीम की वजह से, वह एम०पी० से गेस्ट प्रकामोडेशन एक-दो महीने के लिए हासिल कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए प्रकामोडेशन ले लेते हैं। मगर इन्तहाई प्रफसोस की बात है कि तीन महीने तो छोड़ दीजिए डेढ़-दो साल गुजरने के बादजुद भी वह बिबिंला खाली नहीं करते। तो उसके लिए कुछ एम० पी० की प्रोजीशन भी बड़ी आकवड होती है और साथ ही साथ गबनमेड की प्रोजीशन भी बड़ी आकवड होती है।

महोदया, जितने भी प्रकायाजात रहेंगे, वह उसी एम०पी० के नाम पर आयेंगे, जिस एम०पी० ने दस्तखत करके उसको गेस्ट प्रकामोडेशन दिया है। मगर आखिर उसको खाली करवाने का भी तो कोई जरिया होना चाहिए। अब सिवाय इसके कि सिविल कोर्ट में जाएं और सूट फाईल करें, और जैसा कि आप भल्ली तरह से जानते हैं कि अगर एक हफा सिविल कोर्ट में जाएं, तो चार-छह साल लग जाते हैं और जिस मकसद के लिए मुकदमा दायर किया जाता है वह मकसद ही फीत हो जाता है।

लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि इस प्रोजीशन के तहत जब कि यह अमेंड-मेंट पास हो जाएगा, जोतो खुद हुकूमत की इस बात का अख्तियार होगा कि वह समरी ट्रायल के बाद उसको खाली करवा सके। मगर मेरी रहां एक सजेशन आनपेरेबल मिनिस्टर से यह है—मैं आन-रेबल मिनिस्टर की त्वज्जह चाहंगा, मैडम जरा मैं आपकी त्वज्जह चाहंगा—आपने यह कहा है कि—

"As a corollary to the summary eviction procedure, it is proposed that no appeal should be allowed against the order of eviction passed after summary procedure."

मेरी दरखास्त यह है कि अगर आप अपील का हक नहीं देंगे, तो यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात आएगी।

लिहाजा, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपील का हक जरूर दीजिए।

दूसरी बात यह है कि चौबीस घंटे के नोटिस का जो बात कही गई है, यह भी बेवजूरल जस्टिस के खिलाफ है मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि बजाए चौबीस घंटे के सात दिनों का टाइम दिया जाए।

इन चंद सजेशंस के साथ मैं फिर एक बफा इस बिल की ताईद करता हूँ और जो मुझे टाईम दिया गया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

شرعی محمد خلیل الرحمن آند میرا پریشین  
میدم وائس چیئرمین - ری پبلک پریسیڈنٹ  
(اکونیشن آف ان اتھارٹریٹڈ آن کیو مینٹس)  
آمنڈمنٹ بل ۱۹۹۲ء کی میں تائید کرتا  
ہوں۔ اس وجہ سے کہ یہ کالونی ضرور ہے  
اور موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے  
کہ یہ بل پاس کیا جائے مگر میں آئین بل  
منسٹر سے پوچھنا چاہوں گا کہ پانی سر سے  
اُونچا ہونے کے بعد آپ یہ بل لائی ہیں۔  
۱۹۶۱ء میں یہ ایکٹ بنا تھا۔ گو یہ آج  
سے ۲۱ سال پہلے۔ اس عرصہ میں کئی ایسے  
ناچائز قبضہ دار این بلڈنگوں میں آ گئے۔  
مگر اس کے باوجود ۲۱ سال تک آپ بیٹھے  
رہے۔ اب جبکہ مسئلہ انتہائی ٹیڑھا اور پیچیدہ  
ہو گیا ہے تو یہ بل لایا گیا ہے۔ خیر دیر آئے۔  
درست آئے۔ ایک اچھا بل ہے اور اس  
لئے میں اس بل کی تائید کرتا ہوں۔

یہ جو بل لایا گیا ہے۔ خاص طور سے اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایسے پریسینز ہیں جو کہ دہلی یا یونین ٹیروٹریز میں ہیں۔ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوتا۔ لہذا اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک زمانے سے مطالبہ تھا کہ اس قانون میں اس ایکٹ میں امینڈمنٹ لایا جائے اور پھر اسٹیٹ گورنمنٹس کو بھی اس بات کا اختیار دیا جائے کہ یہاں پر ان کے جو پریسینز ہیں وہ ان پریسینز کو خالی کر سکیں۔ انتہائی قیمتی جائیدادیں یہاں پر اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آندرہ پرادیش کی ہی بات کر رہا ہوں جو یہاں کا حیدر آباد ہاؤس ہے وہ اس وقت منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا نمبر ایک گیسٹ ہاؤس ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راسٹر پتی بھون اور پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کے بعد جو سب سے بہترین بلڈنگ اس وقت دہلی میں ہے وہ حیدر آباد ہاؤس کی ہے۔ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ مگر اس کے باوجود منسٹری گورنمنٹ ان اتھارائزڈ طریقہ سے اس بلڈنگ پر قابض ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے فوراً حیدر آباد ہاؤس کو آپ اسٹیٹ گورنمنٹ

کے حوالے کر دیجئے جو تعلق ٹیگیشن چل رہے ہیں۔ مگر قانون بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ حیدر آباد ہاؤس کو تخلیہ کر سکے۔ یہ بہت اچھا قانون ہے پھر دوسری بات۔ جیسا کہ گیسٹ اکامیڈیشن کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ یہ جنرل شکایت ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض ایسے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے۔ بچوں کی تعلیم کی وجہ سے۔ وہ ایم پیز سے گیسٹ اکامیڈیشن ایک دو مہینے کے لئے حاصل کر لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تین مہینے کے لئے وہ اکامیڈیشن لے لیتے ہیں۔ مگر انتہائی نفوس کی بات ہے کہ تین مہینے تو چھوڑ دیجئے۔ ڈیڑھ دو سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بلڈنگ کو خالی نہیں کرتے تو اس کے لئے مجھے ایم پیز کی پوزیشن بھی بڑی اکیورڈ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی پوزیشن بھی بڑی اکیورڈ ہوتی ہے۔

مہود یہ جتنے بھی بقایا جات رہیں گے وہ اس ایم۔ پی۔ کے نام پر آئیں گے۔ جس ایم پی نے دستخط کیے گیسٹ اکامیڈیشن دی ہے۔ مگر آخر اس کو خالی کر دینے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اب سوائے

اس کے کہ سول کورٹ میں جائیں اور سول  
فائل کریں اور جیسا کہ آپ اچھی طرح  
سے جانتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ سول کورٹ  
میں جائیں تو چار چھ سال لگ جاتے ہیں  
اور جس مقصد کے لئے مقدمہ دائر کیا جاتا  
ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس  
پروویژن کے تحت جب کہ یہ امینڈمنٹ  
پاس ہو جائے گا تو خود حکومت کو اس  
بات کا اختیار ہوگا کہ وہ سرٹیکل کے  
بعد اس کو خال کر دے اسکے منگے میری یہاں  
ایک سبجیشن آئریبل منسٹر سے یہ ہے میں  
آئریبل منسٹر کی توجہ چاہوں گا۔ میڈم۔  
ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ نے یہ  
کہا ہے کہ۔

“As a corollary to the summary  
eviction procedure, it is proposed  
that no appeal should be allowed  
against the order of eviction passed  
after summary procedure.”

میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اپیل  
کا حق نہیں دیں گے تو یہ نیچرل جسٹس  
کے خلاف بات جانتے گی۔ لہذا میں آپ سے  
درخواست کروں گا کہ آپ اپیل کا حق  
ضرور دیجئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو میں گھنٹے  
کے نوٹس کی جو بات کہی گئی ہے یہ بھی  
نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ میں آپ سے

درخواست کروں گا کہ بجائے جو میں گھنٹے  
کے سات دنوں کا ٹائم دیا جائے۔

ان چند سبجیشن کے ساتھ میں پھر  
ایک دفعہ اس بل کی تائید کرتا ہوں اور  
جو بھی ٹائم دیا گیا ہے اس کے لئے میں  
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔  
”ختم شد“

SHRI JAGMOHAN (Nominated):  
Madam Vice-Chairman, thank you  
very much. I will mention very  
briefly a few points. The need for  
the Bill is obviously there, and I sup-  
port it. But one thing I would like  
to mention from my experience is  
that passing of a law is one thing and  
its implementation is totally another  
thing. So, many laws have been pas-  
sed in regard to the land encroach-  
ments, unauthorised occupation, etc.,  
but no law has been effectively im-  
plemented and we see lakhs and lakhs  
of places in unauthorised and illegal  
occupation. Why is it so? It is be-  
cause of lack of respect for the law  
that has developed in the country.  
If you occupy illegally something  
then the feeling is that you will get  
it regularised. It will be all right.  
If the executive is very firm then  
you can always get relief from the  
judiciary. You may pass laws but  
the jurisdiction of the civil court,  
though restricted, is there. The juris-  
diction of the civil court is used  
in all civil matters like this  
and in prosecution proceedings.  
But you will find the courts  
are always interfering, issuing  
stay orders, whether you go in writ  
petition or in some other manner, and  
for years together the cases will not  
get settled. My suggestion in this  
regard is that, apart from showing a  
firm will, you will have to take a  
decision to introduce a judicial audit.  
There should be a commission com-  
prising retired Chief Justices. Like

our Comptroller and Auditor General, we can have a Comptroller and Auditor General for the judiciary. Why don't you do that so that judiciary acts in a responsible way? It is not an interference in the judiciary. Suppose, I am the controller, I can go and see a file of the court, whether the court has interfered in a proper and just way. I know, in Delhi, thousands of stay orders have been given without even asking whether you have got the plan sanctioned from the Corporation, without even asking whether you have applied for it. The stay order is given and it stays for years together and in the meanwhile manipulation goes on, pressure develop but nothing is done. Why should the jurisdiction of the civil court, facilitate these types of things?

Every organ of the Government, every organ of the society must function in a responsible way, if you really want to have the results. If you come with me in the courts, I can show you hundreds of files which are being dealt with in an improper manner where the maturity and responsibility that is expected of the judiciary is not being shown. Therefore, this is the crux of the problem. Let us not sidetrack this issue. Another suggestion which I would like to make is, when a person is occupying unauthorisedly—supposing 'X' or some high official—it should be made clear that, irrespective of the stay order, irrespective of whatever reason he may have for continuing, penal rent will have to be paid. After every week rent should be doubled. Even if you are able to get a stay order and the house is vacated after six months, you will have to pay that much extra rent. So this will act as a disincentive. These are the practical ways by which you can really solve the problem of getting your premises vacated and seeing that the right person gets the allotment. Now-a-days the issue is, somehow or other, you put pressure and get a stay order and get so many other things and nothing will happen.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): I was at first unable to believe my eyes that this lady was able to bring such a harsh law for eviction of people. Now, from the discussion, the enormity of the problem has very much been appreciated. Servants' quarters, MPs' quarters, ex-MPs' quarters, ex-Ministers' quarters, everything has come. As I could see, the amendment relates to temporary occupation for a period not beyond one month—somethink like that—for which eviction process has been laid down. This is an amendment Bill. Therefore, other provisions are definitely there. But the previous speaker, Mr. Jagmohan, was, of course very correct. He repeated an old saying in a different language. Foreign Economists remarked that India is a country where there is no dearth of law, where there are all types of social legislation, but no implementation. The unauthorised occupants are comfortable in the belief that even after such an amendment Bill, such epoch-making amendment, the situation will more or less continue to be the same. Just today I heard something which practically struck me dumfounded. Someone had come yesterday to ask for subscription for some Pooja. I was told that he was threatening. Earlier he was satisfied with Rs. 10. I remained alone in the house, therefore, I used to pay him Rs. 10. Now, he is demanding Rs. 101. Who are these people? They live in Jhuggi-jhompris around the MP's quarters on Ferozshah Road and there is nothing to prevent them. This is not the only problem. There are servant's quarters and the problem was related by Mr. Swaminathan. MPs are sometimes completely unaware that there are so many servants, somehow or the other they occupy them. The House Committee says that it is not possible for them to hand over the servants' quarters. These are all very peculiar problems which are related to this question. So far as the limited purpose of the

[Prof. Soumen Bhattacharya]

Bill is concerned Mr. Santosh Kumar Sahu has very rightly raised the question of cheap accommodation for the bulging population of the capital. There are other related problems which require urgent attention and my only expectation would be that our soft-hearted Didi would deal with these problems also. Thank you.

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Madam, I am grateful to the hon. Members who have participated in this discussion this afternoon. Some of the hon. Members have given very good suggestions. I am obliged to them that they have all agreed in principle with the Bill which has been brought. The Bill is going to facilitate the Members and their guests because now if they have one guest staying in one premises or in the Western Court for 5, 6 or 10 days, the next guest can also come after 7-8 days. If there is a permanent guest staying there for months and months, then the hon. Member will have only one guest staying there in that room. Now, more friends of hon. Members, more number of guests, can come to Delhi for treatment or for whatever purpose they want. This Bill which has been brought here is for General Pool and MPs' houses are not included in this. It only covers guest-houses and temporary allotments. This has to be borne in mind that this is only for temporary allotments and not for permanent residence of over 5 years. It does not include the houses where hon. Members or Ministers live. So, in respect of this we have to find out ways and means in the case of houses that are found to be sublet. Occasionally inspections are conducted and if it is found that the house has been sub-let—then eviction takes place and the allottee concerned, for the rest of the term will not be allowed to live in that house.

4 p.m.

And there are penalties for people...

**SHRI SIKANDER BAKHT**  
(Madhya Pradesh): Doesn't this Bill

cover those houses where the MPs have overstayed?

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTHI NATARAJAN):** No.

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** No; I will come to that also. And for this summary procedure, there is no appeal to civil courts. Only High Court has jurisdiction in this. Now, Kaldateji has gone.

**The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai, in the Chair):**

The State Government premises including the Delhi Union Territory premises will be administered by Estate Officers appointed by the Central Government on the recommendation of the respective State Governments. The amendment will help to evict unauthorised guests of MPs also and relieve them of payment of charges. Then the amendment covers only temporary accommodation, as I said before, and for regular allotment, there is no charge proposed.

My other friends have given some good suggestions. I would like to thank Mr. Vishvjit P. Singh—he has also gone—for giving us a very useful information which, I must say, I did not possess myself. My office must have had it. But he has got it. He is quite right when he says that we should have more houses and other Members have also suggested that.

**SHRI VISHVJIT P. SINGH:** I am very sorry. The TV monitors were showing the result. They were not showing as to who was speaking. That is why I got late.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** She was saying that you have given a very good suggestion.

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Actually, we did construct Type IV flats numbering 256 at Andrews Ganj. But as soon as they were ready, so

many of them demanded and they were taken away like hot cakes. So, to say that we are not constructing is not correct. We are doing the job. But it is difficult to get finance and other things. And constructing of more houses is not covered in this Bill. But it is in our mind.

Some Members said that we must have more bhawans and that the State Governments must construct more bhawans here. Some are doing this and some have asked for more land and we are providing them with land. If they come forward and ask for it, we shall try to help them.

A mention was made about the flats on Baba Kharak Singh Marg. I also went round to see them. I found them very satisfactory. There are three bed rooms, one guest room, a combined drawing and dining room. They are very nice and very comfortable. Well, if you want to scrub your utensils sitting down, then it is a different thing. There, I think, we can have a small suggestion. One tap can be fixed at the top and another tap can be down so that anybody washing the utensils can sit down and do the job. This suggestion can be considered at the time of future construction. We have our own way of living and we do not want to impose our way of living on others.

This amendment will help us to evict unauthorised guests of MPs also and relieve them to payment of charges, as I said before. Do you want me to reply to any other question?

**SHRI V. NARAYANASAMY** (Pondicherry): What about unauthorised constructions?

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** नहीं यह तो दूसरी चीज है।

This is a different thing. You have not studied the Bill.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** Madam, I went through the Bill.

You know that in Delhi, in many areas, a lot of unauthorised and illegal constructions and encroachments are going on. That aspect also comes under your Ministry and you are answerable for that.

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Sir, many honourable Members have spoken on this Bill and have given their suggestions. His suggestion can be considered when I place the National Housing Policy before the House.

**SHRI V. NARAYANASAMY:** That is right.

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Sir, I am grateful to the honourable Members for having given me their thoughts and ideas and I hope that we would be able to do our job with their kind help. Mr. Kaldate said that it was no use doing this unless we all got together to implement the whole thing. We must have the desires and the will to do this and only then we can have it done.

With these words, Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

**SHRI ASHIS SEN:** Sir, I wanted to have a clarification. Even after her reply, one point remains. Sir, I have tabled an amendment. I do not want to give unbridled power to the Estate Officer because there is always the likelihood of its being misused. That is why I have tried to persuade the Minister to have the four words "is of the opinion" replaced by the words "finds on the basis of facts and documents". I would request the honourable Minister to give a favourable response to this.

I also have mentioned incidentally—it has nothing to do with this Bill—about the payment of dues for buildings in Calcutta. Of course, that is a separate matter.



**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Really I cannot catch his point.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** You can consider it at the time of moving the amendments. Now, I will put the motion to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act, 1971, be taken into consideration."

The motion was adopted.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—Insertion of new section 3A.

**SHRI KRISHAN LAL SHARMA (Himachal Pradesh):** Sir, I beg to move:

"That at page 3, after line 9, the following proviso be inserted, namely:—

"Provided that the entire process of eviction from temporary occupation of any public premises shall not exceed thirty days from the date of expiry of the period of allotment, including the extended period, if any."

The question was proposed.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा संशोधन रखना चाहता हूँ। कई दिनों ने कहा भी है कि वैसे तो हमने धारा-3ए में यह प्रावधान किया है कि चौबीस घंटे का पहले नोटिस दिया जाएगा। जब उसका समय खत्म हो जाएगा या उसका जो एक्स्टेंडेड टाइम है वह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें हैं, जो इस्टेड अप्रॉक्सि-

मैं वह उनके घर जाएँ। वह कब जाएगा, कितना समय लेगा, कौन सा टाइम फिक्स होगा इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है? फिर उसके सेटिसफैक्शन का साबल है। इसमें वह कितना टाइम लेता है, इसके बारे में यद्यपि दोनों बार हमने यह कहा है कि हम चौबीस घंटे के अंदर निरीक्षण का आर्डर पास करेंगे। लेकिन बीच में ऐसा लकूना है कि जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं होगा और इसलिए मैंने अप्रॉक्सिमेट पेश किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना कि वे इस पर विचार करें।

**SHRIMATI SHEILA KAUL:** Well, he has given his viewpoint. I do not think I have to say anything now.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** Mr. Sharma, she will consider it in future. You are insisting on your amendment?

**SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** At least some assurance from the Minister is necessary because we take so much time and there is no provision to see that we try to finish all the processes within thirty days or so.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** She has assured that she will look into it. I think, you should be satisfied with that.

**SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Okay. I am not insisting on my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI):** I shall now put Clause 3 to vote. The question is:

"That clause 3 stand part if the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

*Clause 4 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up the Indo-Tibetan Border Police Force Bill, 1992.

### THE INDO-TIBETAN BORDER POLICE FORCE BILL, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the constitution and regulation of an armed force of the Union for ensuring the securities of the borders of India and matters connected therewith, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, the Indo-Tibetan Border Police was raised in October, 1962 in the wake of Chinese aggression on our Northern borders. The Force was conceived as an integrated unconventional Guerilla-cum-intelligence-cum-fighting Force meant to operate primarily in the inhospitable, wild and vertical world of the Himalayas. Since its inception, it has been mainly deployed ahead of Army defences in the remote areas of Northern borders at altitudes of 9,000 to 19,000 ft. above the sea level in the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. It has been discharging its role, including border surveillance, effectively. Moreover, during

the past three decades, it has also acquired a rich experience in the fields of high risk VVIP security duties, banks security duties and in anti-terrorist operations in States like Jammu & Kashmir and Punjab. The specialisation acquired by ITBP has accorded it a recognisable identity of its own.

The ITBP, since its raising, is being governed by the provisions of the CRPF Act, 1949 and the CRPF Rules, 1955 as amended from time to time. However, the role of ITBP is distinct from that of CRPF, as it includes providing a sense of security to the population living on the borders, controlling trans-border traffic, ensuring effective border surveillance and functioning under the operational control of the Army as may be required in sensitive areas. This role demands legal provisions of a nature somewhat different from those required by the CRPF. This is the background in which the Indo-Tibetan Border Police Bill, 1992 has been introduced. A separate Act would also impart a sense of pride and recognition to the ITBP personnel. With these words I commend this Bill to this august House for approval.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is one amendment by Shri Krishan Lal Sharma for reference of the Bill to the Joint Committee of Parliament.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना हूँ कि इस बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को रेफर किया जाए। जैसा कि श्री बनाया गया यह बहुत बड़ा बिल है 157 कलाब्रैज है, 30 साल के बाद वह बिल लाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस पर और विस्तृत विचार होना चाहिए और जल्दी बाजी में इसको पास नहीं करना चाहिए। तीस साल के बाद यह बिल लाया जा रहा है और फिर अधूरा रह जाए यह उचित नहीं है। इस लिए मैं अपना संशोधन दे रहा हूँ कि इसको दोनों सदनों की संयुक्त समिति